कृपया प्रकाशनार्थ - **29 मई 2012**

भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक द्वारा 29 मई 2012 को नागपूर में पत्रकार परिषद में किया वक्तव्य

''पेट्रौल दामवृद्धि - वित्तिय अराजकता की ओर'' - राम नाईक

नागपूर, मंगलवार : ''पेट्रोलियम के इतिहास में हालही में हुई प्रति लीटर रु. 7.50 की दामवृद्धि अभूतपूर्व है, उसके कारण वित्तिय अराजकता पैदा होगी. महंगाई वृद्धि का दुष्टचक्र और अधिक गतिमान होगा. डॉलर की तुलना में रुपैये का मूल्य निचे जा रहा है, जिससे आग और भडक रही है. इसिलिए यह दामवृद्धि पिछे लेने की माँग को लेकर भाजपासहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सभी पार्टीयों नें जनआंदोलन छेडा है. गुरुवार 31 मई को जनता स्वयंस्फुर्ती से भारत बंद में शामिल होकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दें'', ऐसा आवाहन भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने किया है. वें आज नागपूर में पत्रकार परिषद में बोल रहे थे.

''भारत सरकार के इस संवेदन शून्य निर्णय का अगर अभी डट कर विरोध नही किया तो डिज़ल, घरेलु गैस और केरोसिन के दाम भी बढा कर यह सरकार आम आदमी का जिना मुश्किल कर देगी'', ऐसी चेतावनी भी श्री. राम नाईक ने दी है.

पेट्रोलियम वस्तुओं के दामों के संदर्भ में अपनी भूमिका बताते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,''आंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कुछ मात्रा में बढे है इसमें कोई संदेह नही. किंतु ऐसी परिस्थिती में आयात तथा अबकारी करो में घटौती कर ग्राहक पर का दामवृद्धी का बोझ कम किया जा सकता है. किंतु वित्त मंत्री श्री. प्रणव मुखर्जी को दामवृद्धी के कारण मिलने वाली अधिक आय में ही ज्यादा रुचि है. जरुरी है कि भारत सरकार सभी करों से मिलने वाली अधिक आय में कटौती करें और ग्राहकों को राहत दे. अंग्रेजी में इसे 'रेव्हेन्यू न्यूट्रल' नीति कहा जाता है. प्रधान मंत्री श्री. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यही नीति अपना कर हमने जनता को राहत दी थी.''

''केवल भारत में ही नहीं तो दुनिया के कई अविकसित तथा विकसित देशों में कच्चा तेल आयात किया जाता है. मुंबई में पेट्रोल के दाम बढ कर अब प्रति लिटर रु. 78.57 है, तो अपने पडोसी देशों में; पाकिस्तान में रु. 59.00 (रु. 19.57 कम), श्रीलंका रु. 61.70 (रु. 16.87 कम), और बांगलादेश में रु. 43.40 (रु. 35.17 कम) प्रति लीटर दाम से पेट्रौल मिलता है. विकसित देशों में भी जैसे अमरिका में रु. 53.70 (रु. 24.87 कम) और रुस,मास्को में रु. 50.20 (28.37 कम) पेट्रौल के दाम भारत से कम ही है. इससे यह स्पष्ट है कि अपने करों की पुनर्रचना कर दामवृध्दी में कटौती करना सरकार को संभव है,'' ऐसा भी श्री.राम नाईक ने कहा.

..2..

प्रधानमंत्री श्री.अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में देश की अवश्यकता का 70 प्रति शत कच्चा तेल आयात किया जाता था. अब यह मात्रा बढ कर लगभग 80 प्रति शत कच्चा तेल आयात होता है, ऐसी जानकारी देकर श्री.राम नाईक ने आगे कहा,''कच्चे तेल के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता अब खतरे की सीमा से कहीं अधिक है. यह निर्भरता कम करने के लिए प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई कदम नही उठाए है. प्रधानमंत्री श्री.वाजपेजी की सरकार ने जनता के हित के लिए पाईप गॅस, बायोडिझल, इथेनॉल जैसी अनेक परियोजनाएं शुरु की. इतनाही नही तो सीधे विदेशों में भी निवेश किया. हमने रशिया के साखालिन के तेल क्षेत्र में रु.8,500 करोड, तो सुदान में रु.3,200 करोड निवेश किया. इन दोनों क्षेत्रों से भारत को तेल मिलना भी शुरु हुआ है. मगर डा.मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐसी कोई योजना हात मे नही ली.वाजपेयी सरकार ने तो उत्खनन की योजनाएं भी बना कर कृष्णा - गोदावरी घाटी में प्राकृतिक गैस तथा राजस्थान में कच्चे तेल ढूंड निकाला.वहाँ भी उत्पादन शुरु हुआ है. मगर डा.मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐसा कुछ भी नही किया उलटा इन दोनों जगहों पर भी उत्पादन में दिक्कते पैदा होती हुई नजर आती है.''

''पेट्रौल में बतौर पूरक इंधन मिलाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग करना वाजपेयी सरकार ने शुरु किया. गन्ने के शिरे से इथेनॉल बना कर वह 5 प्रति शत तक पेट्रौल में मिलाने का ऐतिहासिक निर्णय वाजपेयी सरकार ने किया. वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही 1 जनवरी 2003 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रौल की बिक्री भी शुरु हुई. आगे चलकर इथेनॉल की मात्रा 10 प्रति शत तक बढाने का निर्णय हुआ था. यह निर्णय गन्ना उत्पादक करनेवाले किसानों को नयी संजीवनी देगा, ऐसा अभिमत यह योजना का प्रारंभ होते समय आज के कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने व्यक्त किया था. इस निर्णय के चलते विदेशी मुद्रा में तो काफी बचत होनेहीवाली थी, साथ ही साथ किसानों को उनके गन्ने के लिए अधिक मूल्य प्राप्त होकर उन्हे तथा इथेनॉल बनानेवाले कारखानों को भी काफी मुनाफा मिल सकता था. मगर वाजपेयी सरकार गयी और डा.मनमोहन की सरकार आयी. आते ही यह सरकार लिकर लॉबी के दबाव के आगे झुक गयी और इथेनॉल की खरीदारीही इस सरकार ने बंद कर एक अच्छी खासी योजना बंद कर दी. अब सात साल बाद इस योजना की उपयोगिता ध्यान आ रही है. उस पर फिर से अंमल करने पर विचार हो रहा है ऐसा बताया जाता है. किंतु इस बीच सात साल गन्ना उत्पादक किसान, शक्कर बनाने वाले कारखानदार तथा पुरे देश का जो भारी नुकसान हुआ उसके लिए क्या अर्थतज्ञ प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह जिम्मेदान नही है ?'', ऐसा सवाल भी श्री.राम नाईक ने पूछा.

पेट्रोलियम पदार्थां के मूल्य निर्धारण के लिए डा.मनमोहन सिंह सरकार की कोई ठोस नीति नही ऐसी आलोचना करते हुए श्री.राम नाईक ने कहा,''वित्तिय उदारता की नयी नीति के अनुसार पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जब डा.मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और श्री.पी.व्ही.नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब उच्चस्तरीय तज्ञ समिती का गठन किया गया था. बाद में कॉंग्रेस के समर्थन पर चल रहे

देवेगौडा सरकार ने इस समिती का अहवाल मंजूर किया और मार्च 2002 से चरणों में पेट्रोलियम पदार्थों पर का नियंत्रण हटाने का निर्णय हुआ. इसी निर्णय पर अंमल करते हुए वाजपेयी सरकार ने पेट्रौल और डिजल के दामों पर से नियंत्रण हटाया हर 15 दिन बाद आंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढाव देख कर भारत की तेल कंपनियों ने ग्राहकमूल्य मे आवश्यक उतार - चढाव करना शुरु किया. किंतु मई 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने सत्ता पर आते ही इस नीति को तथा सूझबूझ को बाजू में रख कर कामचलाऊ (एड-हॉक) रवैया अपनाया. अपनी मनमर्जी से दाम तय करना शुरु किया. आखिर 6 वर्ष बाद याने जून 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रौल पर का नियंत्रण तो हटाया किंतु डिजल को नियंत्रण में ही रखा, जिससे इस क्षेत्र की और भी दुर्गती हुई. युपीए सरकार के कार्यकाल में तीन पेट्रोलियम मंत्री हुए. पहले श्री.मणिशंकर अय्यर, बाद में श्री.मुरली देवरा और अब श्री.जयपाल रेड्डी. इन में से एक ने भी स्पष्ट नीति न अपनाने से इस संवेदनशीन क्षेत्र में अस्थिरता निर्माण हुई है.'' ऐसी जानकारी श्री.नाईक ने दी.

''पेट्रोलियम वस्तूओं के हर दम बढते दामों के कारण जीवनावश्यक चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे है. दाम वृध्दी के दुष्ट चक्र की गति बढती जा रही है. मई 2004 में प्रति किलो रु. 9 से गेंहू मिलता था, अब उसका दाम रु. 22 (144% बढत) हुआ है, चावल रु.10 से रु.24 (140% बढत), दूध रु.14 से रु.36 (157% बढत), शक्कर रु.14 से रु.35(150% बढत), चाय रु.80 से रु.250 (212% बढत), गूड रु.14 से रु.43 (207% बढत), अरहर रु.30 से रु.70 (133% बढत), तेल रु.40 से रु.98 (145% बढत) महंगे हुए है. सब्जियों की महंगाई के बारे में सोचही नहीं सकते. ऐसे में आम आदमी पेट भरने के लिए क्या खाए ?,'' ऐसा सवाल भी श्री.राम नाईक ने किया.

''मानो यह दिक्कते कुछ कम थी इसलिए रिजर्व बैंक ने पिछले डेढ वर्ष में 13 बार ब्याज के दर में बढोतरी की है, और डॉलर की तुलना में रुपैये में जो गिरावट आ रही है वह अलग. अप्रैल 2011 में रु.44.50 से अब मई 2012 में रुपैये का अवमूल्यन 56 तक याने 26 प्रतिशत हुआ है. यह सारा बोझ आम आदमी को सहना पड रहा है. अब इस अन्याय को हम अधिक नही सहेंगे. पेट्रौल की दामवृध्दी तुरंत वापस ली जाए इस माँग के लिए गुरुवार 31 मई को 'भारत बंद' का ऐलान किया है. देश की जनता स्वयंस्फुर्ति से इस 'भारत बंद' में शामिल हो,''ऐसा अनुरोध भी अंत मे श्री.राम नाईक ने किया है.

(कार्यालय मंत्री)